असम की हिंसा पर सहानुभूति से भी अधिक सोचने की जरुरत

– सुनील आंबेकर

इस बार 20 जुलाई से ही असम के बोडो क्षेत्र के हिंसाग्रस्त होने की बडी बडी खबरे आने लगी, लेकिन देश में अधिकतम लोगो के मन में उतनी बडी प्रतिक्रिया नहीं थी। असम हिंसा का दौर लगातार ही चल रहा है तथा 2008 में भी बोडो क्षेत्र के उदालगुडी व अन्य क्षेत्र में हमले हुए तथा एक लाख से अधिक लोग पिड़ित शिविरों में रहने पर मजबूर हुए थे। परन्तु इस बार जब दोनों तरफ झड़पें चलती रही तथा घुसपैठियों को भी कुछ क्षेत्र छोडना पडा, तब उनके समर्थकों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन अन्यत्र प्रारंभ किया। विशेषकर मुंबई में 'अल्पसंख्यको पर अत्याचार' के घोषवाक्य की आड में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में रजा अकादमी के तत्वाधान में हिंसक प्रदर्शन दि. 11 अगस्त 2012 को आयोजित हुआ तथा बाद में देशभर में अध्ययन कर रहे छात्र या रोजगार में लगे हुए पूर्वोत्तर के लोगों को धमकाया गया तथा तत्काल अपने घर वापस जाने के लिए उन्ही घुसपैठियों के समर्थकों द्वारा मजबूर करने का प्रयास किया गया, परिणाम स्वरुप देश के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, पुणे, हैदराबाद, राँची, बैंगलोर आदि स्थानों से मुंबई के प्रदर्शन के तत्काल पश्चात पूर्वोत्तर वापसी हेतु पलायन प्रारंभ हुआ। दोनो घटनाओं ने देशभर के लोगों को झकझोर कर रख दिया तथा घुसपैठीयों व उनके समर्थक किस हद तक जा सकते है, इसका भयंकर चेहरा उजागर हुआ। इन घटनाओं ने पुरे देश को हिला दिया तथा उस संकट की गंभीरता ने सभी की चिंता बढा दी।

घटनाओं को अलग–अलग देखने की जगह जोडकर देखने से साफ तौर पर षडयंत्र दिखायी पडता है। विभाजन के पश्चात लगातार बांग्लादेशी से सटी खुली या तटस्थ सीमा से लाखो घुसपैठियों ने अवैध तरीकों से भारत में प्रवेश किया। यह कई बार कहा जाता है कि वे लोग रोजगार की तलाश में यहाँ आते है। लेकिन यह जबाब कोई नहीं देना कि रोजगार के लिए वैध तरीके से आने का मार्ग उपलब्ध होने पर भी यह अवैध रास्ता क्यों अपनाया जाता है?

घुसपैठियों को अवैध रुप से लाने वाले लोगों के एजेट सीमा के दोनों तरफ उपलब्ध है। अवैध घुसपैठ द्वारा असम के क्षेत्र में जनसंख्या संतुलन अपने पक्ष मे करते हुए अंतत: असम को भारत से तोडने का यह षडयंत्र है। 1947 में हुए भारत विभाजन की पूर्व घटनाओं का क्रम जोडने से लगता है, जैसे वहीं बातें किसी सिक्वेल में बनी हिंदी, फिल्म की तरह दोहरायी जा रही है और हम है कि अभी भी गुढ कहानी की तरह देख रहे है। एक – एक क्षेत्र को मुस्लिम बहुल बनाना, फिर वहाँ दहशत फैलाना, अन्य मूलरुप स्थायी लोगों को वहाँ से दंगा करते हुए भगाना, अलग विशेष क्षेत्र की मांग, अल्पसंख्यक होने का दावा करते हुए अत्याचार से पिडीत होने का दावा करना, अपनी मतदाता संख्या के आधार पर राजनैतिक दलों को लुभाना एवं सत्ता तथा प्रशासन पर दबाव बनाना एवं इस मार्ग में कई सारे अवैध कार्य जैसे तस्करी, ड्रग्स, शस्त्र बिक्री, जाली नोट, महिलाओं को भगाना, जमीन लूटना, मंदिरो जैसे अन्य प्रार्थना स्थलों को क्षति पहुँचाना, स्थानीय मुस्लिम समूदाय में भी दहशत फैलाकर रखना यह करते हुए आगे बढना व अंतत: देश से उस हिस्से को तोडना। बिल्कुल वहीं कहानी कई वर्षों से असम व सीमावर्ती क्षेत्र में यह विदेशी सूत्र चला रहे है। दुर्भाग्य यह है कि अब तक तथाकथित धर्म निरपेक्षता के नाम पर अपनी वोट बैंक की खातिर अल्पसंख्यकों की रक्षा का बहाना देते हुए न तो सीमाओं को ठीक से बंद किया गया, न ही घुसपैठियों की पहचान करते हुए उन पर कारवाई की गयी। परिणाम स्वरुप आज असम की कुल 3 करोड की जनसंख्या में अवैध तरीके से 60 लाख लोगों ने अपना नाम बढ़ा दिया है तथा कई उस प्रयास में कतार में है।

अभी हाल ही में असम के बोडो क्षेत्र में हुई हिंसा कोई स्थानीय विवाद से उत्पन्न नही हुई अपितु इसी व्यापक षडयंत्र के तहत घर एवं खेती की जमीनें हडपने, संरक्षित जंगल के क्षेत्र में भारी कब्जा करने से प्रारंभ हुई। जिसका मुख्य उद्देश्य दहशत फैलाकर अंतत: धुबरी की तरह शेष कोकराझार आदि क्षेत्र से भी बोडो जनजाती को हटाते हुए उस क्षेत्र पर पुरी तरह कब्जा करना था। कश्मीर घाटी की तरह वह लोग जिसमें बोडो, अन्य जनजाती, बांग्ला एवं अन्य भाषी लोग आदि सभी गैर–मुस्लिम लोगों को उस क्षेत्र से भगाने की योजना की शुरुआत थी।

योजना पुरानी थी, लेकिन अब जनसंख्या का संतुलन, लगातार हुई अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण षडयंत्रकारियों के पक्ष में जा रहा है। स्थानीय भारतीय मुस्लिम समुदाय को भी दबाया जा रहा है। इसके प्रभाव में हाल ही में स्थानीय असम मुस्लिम नेताओं (सदाऔं असम गरिया–मुरिया देशी – SACM) द्वारा जारी बयान में यह कहा गया कि सभी मस्जिदों में बांग्लादेशी मौलवीयों को नियुक्त किया जा रहा है, तथा दंगों के पीछे धुबरी के सासंद बदरुद्दीन अजमल का हाथ है। तथा उसकी घिनौनी देशद्रोही नीति मुख्य कारण है, यह पुरा असम जान रहा है। बदरुद्दीन अजमल द्वारा घुसपैठियों को अवैधरुप से भारत में प्रवेश कराना, उन्हे जाली पहचान पत्र आदि बनवाने में सहायता करना तथा ऐसे मतदाताओं के आधार पर असम में 125 सदस्यों वाली विधानसभा में 18 विधायकों के बल पर पुरे दबाव की राजनीति कि जा रही है। 2005 में प्रारंभ हुए अपने दल (AIUDF – ऑल इंडिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फंड) को 2009 में देशभर फैलाने की घोषणा के पश्चात पुरे देश में फैलाए घुसपैठियों को आधार बनाकर कट्टरपंथियों के साथ मिलकर तनाव उत्पन्न करने का काम वह कर रहा है। इसलिए बदरुद्दीन अजमल को गिरफ्तार करने की मांग पुरे असम में उठ रही है।

वैसे केंद्र एवं असम सरकार ने अनावश्यक रुप से बोडो नेता विधायक श्री प्रमोद ब्रम्ह को जिस तेज गति से गिरफ्तार किया, वैसी तेज गति अजमल के बारे में नही दिखा रही है। फिर बोडो लोगों पर दमन चक्र चलाने की नीति छोडकर वास्तविक अलगाववादी नेता अजमल को गिरफ्तार करना समय की मांग है। कश्मीर में जब परिस्थिति बिगड़ गयी तथा शेख अब्दुल्ला के देशद्रोही इरादे उजागर हुए तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने अपने इस मित्र को अंतत: 8 अगस्त 1953 में गिरफ्तार करते हुए लगभग 10 वर्ष जेल में रखकर वहाँ की परिस्थिति को नियंत्रण में किया। आज बदरुद्दीन अजमल को भी तत्काल जेल की सलाखों के पीछे डालकर उसके षडयंत्र का पर्दाफाश करते हुए असम को बचाने की जरुरत है।

बदरुद्दीन अजमल असम के दंगाखोर घुसपैठीयों एवं मुंबई में आजाद मैदान के दंगाखोर तथा देशभर में असम एवं पूर्वोत्तर सभी लोगों में दहशत फैलाने वाले यह सब एक षडयंत्र का हिस्सा है। इन सभी को एक साथ देखने की जरुरत है।

साथ ही जो बुद्धिजीवी, राजनैतिक दल, मानवाधिकारवादी, पत्रकार आदि इन सब घटनाओं के सच को तोड मरोड़कर प्रस्तुत करते हुए अलगाववादियों का समर्थन करते है, वह ज्यादा खतरनाक है। क्योंकी वह ऐसा वातावरण तैयार करते है, की प्रशासन उन पर कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता व घुसपैठिये खुले आम घुमते है। ऐसे लोगों के विरोध में व्यापक जनमत की आवश्यकता है।

हमारी सेनायें सीमा पर दुश्मनों से लडने में पुरी तरह सक्षम है लेकिन देश के अंदर के छुपे दुश्मनों को जनता को पहचानना जरुरी है इन्हे हमें रोकना होगा। भ्रामक विचारों का पर्दाफाश हमें करना होगा। इसलिए बोडो या समूचे पूर्वोत्तर के लोगों के प्रति सहानुभूति रखना पर्याप्त नहीं होगा, हम सभी देशवासियों को उससे अधिक सोचने की जरुरत है।

(लेखक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठनमंत्री है।)